



पत्री और चार बेटियों की हत्या का आरोपी बदलूद्धीन गिरफ्तार

पुलिस के पकड़ते ही खा लिया जहरीला पदार्थ

शकुन टाइम्स संवाददाता



लखनऊ। यूपी राजधानी लखनऊ में पुलिस ने भट्टी और चार बेटियों समेत अपने परिवार के पांच लोगों की हत्या करने के एक आरोपी बदलूद्धीन को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चारबाग इलाके में होटल शराजीत में 31 दिसंबर को अपने बेटे अशद की मरद से अपने परिवार की हत्या करने वाले बदलूद्धीन उर्फ बदर को सोमवार को पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने जहरीला पदार्थ खाने की भी कोशिश की, लेकिन तत्काल चिकित्सा

सहायता के बाद वह सुरक्षित है।

अक्षया (16) और रहमीन (18) शामिल हैं। अरशद ने अपने गृहनार आगरा में अपने सूमदार के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा भूमि विवाद को लेकर उत्पीड़न करने का आरोप

लगाया था, जिसके कारण कुछ होकर उसने अपराध करने का दावा किया था। पांच हत्यायों को मामला एक जनवरी को सम्पन्न आए तो उसने बदलूद्धीन को गिरफ्तार कर लिया था।

सोशल मीडिया पर एक कथित

वीडियो में अरशद ने अपनी बहनों और माँ की कलाई और गला रेतने की बात कबूल की। उसने दावा किया कि मोहल्ले के लोगों के उत्तीर्ण के कारण उसने यह कदम उठाया। अरशद ने कहा था, मैं और मेरा पूरा परिवार लाचारी और निशाना में यह कदम उठाने को मजबूर हूँ... मैं अपनी बहनों और माँ को खुद

को मार डाला है।

जागृति सेवा संस्थान

द्वारा भागवत कथा का थुभारंभ

शकुन टाइम्स संवाददाता

यात्रा में सभी महिलाओं ने शास्त्री नगर से कालीमाड़िया से बापस यात्रा शास्त्री नगर में सम्पन्न हुई यात्रा में

कानपुर। शास्त्री नगर में जागृति

सेवा संस्थान की

व्यास्थापक दीक्षा

तिवारी

जी ने

भव्य भागवत

गीत का प्रार्थन

किया पंडित जी

ने श्रीकृष्ण

भगवान का जन्म

गुरु गान किया

इसमें पदाधिकारी

विनायक तिवारी,

गोविन्द गुप्ता,

करन

उत्तरवन्द

उत्तायाय,

अंकित, कृष्ण जी

बाल कलाओं का

वरन किया पंडित

जी ने संस्थान के साथ आज कलश

सभी क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया।



शकुन टाइम्स संवाददाता

बीजपुर में 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत



शकुन टाइम्स संवाददाता

बीजपुर/सोनभद्र। बीजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोडहर के बेलहवा टोला में एक 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है।

16 वर्षीय राजू पाल का शव एक

सीढ़ी बाटे मात्रा में एक 16 वर्षीय

किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में

मौत का मामला सामने आया है।

मृतक के गले पर सोनभद्र



सम्पादकीय

महू से संविधान-दक्षा की निणायिक लड़ाई

अपना पहला चुनाव लड़ाई म इड्यूला अलायस न एनडाएं पर बनाइ बढ़तनई पेंशन या नहीं पेंशन- हंगामा है यूं बरपा ! मध्यप्रदेश के इंदौर के निकट स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की निर्णायक लडाई छेड़ दी, जब सोमवार को आयोजित एक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश की मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों का व्यापक चित्रण करते हुए चेताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, आदिवासियों, एवं कमज़ोर वर्गों के हक को मार रही है। चित्रितों के लिये संविधान के महत्व को समझाते हुए राहुल ने बतलाया कि जिस दिन देश का संविधान खत्म हो जायेगा उस दिन इन वर्गों के लिये कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे तो कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की लडाई पिछले कुछ समय से कई-कई मोर्चों पर और अनेक स्वरूपों में छेड़ रखी है, लेकिन महू की सभा में राहुल ने जिस स्पष्टा व व्यापकता से संविधान की अहमियत प्रतिपादित की तथा उस पर छाये संकर्तां का ब्यौरा दिया, उसके चलते उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस का संदेश इन वर्गों तक ही नहीं वरन् समग्र समाज तथा देश को समझ में आयेगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त कर लोक अधिकारों का सम्पूर्ण खात्मा करना चाहती है। इस सभा में जय बापू जय भीम जय संविधान का जो नारा दिया गया है वह कोई रातों-रात गढ़ा गया अथवा एकाएक सोची गयी थीम न होकर एक वैचारिक प्रक्रिया से निकली हुई यह सोहेश्य लड़ाई है। याद हो कि राहुल ने 7 सितम्बर, 2022 को कन्याकुमारी से लगभग चार हजार किलोमीटर का दौरियां से उत्तर की ओर पैदल मार्च किया था और जिसका समापन कश्मीर के श्रीनगर में 30 जनवरी, 2023 को हुआ था, उसे श्भारत जोड़े यात्राश् का नाम दिया गया था। वह देश में नपरत के खिलाफ मोहब्बत की यात्रा थी। साम्प्रदायिक सौहार्द के लिये निकली उस यात्रा के दौरान अनेक मुद्दों पर राहुल चर्चा करते दिखे जिसमें यह तथ्य सामने आया कि भाजपा एवं उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक खास एजेंडे के तहत देश में ऐसा माहौल बना रही है। एक ओर तो वह हिन्दू-मुस्लिमों को लड़ा रही है तो वहीं वह दूसरी ओर अगाड़ों-पिछड़ों के बीच खाई को चौड़ा करने के बड़े घड़यंत्र और कुचक्र रच रही है। जैसे-जैसे यह यात्रा बढ़ी तो लोगों को यह बत स्पष्ट होने लगी कि इसके पाठे का असली खेल देश के सारे संसाधन मुक्रे भर कारोबारियों को सौंप देने का है।

के दुष्परिणाम ये हैं कि देश में गरीबी, बेकारी और बेहाली छाई है। शिक्षा व स्वास्थ्य सहित सारे जनहित के कार्य ठप पड़े हैं और धर्म व जाति के जरिये भाजपा केवल ध्रुवीकरण में व्यस्त है। विपक्षी दलों सहित सभी तरह की विरोध व असहमतियों की आवाजों को सरकार दबा रही है। आर्थिक शक्तियों पर आधिपत्य करने के लिये भाजपा व उसकी केन्द्र सरकार राजनीतिक ताकत के अपनी मुख्री में ले चुकी है। यह कार्य आसानी से करने के लिये ही उसने सामाजिक ताने-बाने को ध्वस्त कर दिया है। इसलिये जब राहुल गांधी ने उस यात्रा का सीक्षण हाई ब्रीड (पैदल व वाहन के जरिये) के रूप में मणिपुर से 14 जनवरी, 2024 से प्रारम्भ कर दो माह बाद मुम्बई में समाप्त किया, तो उसे भारत जोड़े न्याय यात्रा नाम दिया गया जो समय की आवश्यकता एवं समय के अनुरूप ही था। सामाजिक सौहार्द की लडाई को कांग्रेस ने केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक व आर्थिक न्याय की लड़ाई के रूप में भी बड़ा विस्तार दिया। लोकसभा के लिये पिछले साल के मध्य में हुए चुनाव में भाजपा ने जो 400 पार का नारा दिया था उससे एक तरह से संविधान को पहला बड़ा और साफ खतरा उभरकर आया। वैसे तो पहले से यह दिख रहा था कि भाजपा व संघ की पसंद भारत का संविधान नहीं बरन मध्ययुगीन संहिता मनुस्मृति है। कई मोकों पर वह संविधान की कोसती आई थीं। उसके कई नेता तथा चुनावी प्रत्याशी उसे बदलने की मंशा जतला चुके थे। वे यह कहकर बोट मांग रहे थे कि मोदी को 400 सीटें चाहिये क्योंकि संविधान को बदलना है। इस बात को कांग्रेस व उसके नेतृत्व में बने प्रतिपक्षी गठबन्धन ईडिया के साथ जनता ने भांप लिया जिसके कारण भाजपा की सीटें इतनी घट गयीं कि मोदी को तेलुगु देसम पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। वैसे तो आरोप हैं कि तकरीबन 80 सीटों पर ईवीएम के जरिये हेर-फेर हुआ है। बहरहाल, भाजपा के मंसूबे ध्वस्त होने का परिणाम यह हुआय और भाजपा को संविधान की ताकत का एहसास भी हो गया कि उसे संविधान के आगे सिर झुकाना पड़ा। पिर भी, भाजपा-संघ की संविधान के प्रति वास्तविक श्रद्धा तो कभी थी ही नहीं यो थी वह अस्थायी व कृत्रिम थी। अवसर आने पर उसकी कलई खुलती गयी। राज्यसभा में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्षी सदस्यों पर यह कहकर तंज कसना कि, अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है..., यह बतलाने के लिये काफ़ी था कि भाजपा व संघ संविधान निर्माता का कितना सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने हाल ही में यह बयान दिया था कि च्छेद को असली आजादी 22 जनवरी, 2024 को मिली है श् उनका आशय अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से था।

पिंड्री भी राष्ट्रपति को अपनी ओर से कुछ नया तर्क जोड़ेना ही चाहिए, इस तरह की मांग को तो शायद ज्यादती भी कहा जा सकता है, हालांकि ऐसा होना इस नारे के पक्ष में तर्कों के सतहीपन को जरूर दिखाता है। वरैर! असली बात यह है कि हमारी सर्वेधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद, उअपनी सरकारशृं के शपरमध्यशृं से जिस तरह बंधा हुआ है, उसे देरवते हुए राष्ट्रपति के अपनी सरकार के किसी फैसले का बचाव करने को किसी भी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक एक देश एक चुनाव के प्रोजेक्ट का सवाल है, उस पर राष्ट्रपति मुर्मू की सरकार अंततः अपने अनुमोदन की मोहर ही नहीं लगा चुकी है, वह दो विधेयकों के रूप में इससे संबंधित संशोधन प्रस्तावों को पिछले ही सत्र में संसद में पेश भी कर चुकी है। और इन विधेयकों को और विचार के लिए, संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजा भी जा चुका है।

राजेन्द्र शम

बेढब तो है, पर हैरान नहीं करता है कि गणतंत्र की पूर्वसंध्या पर अपने परंपरागत संबोधन में राष्ट्रपति मुम् ने शहदेश, एक चुनावश का जी भरकर गुणगान किया। उन्होंने इसे अपनी सरकार का शसाहसरूप दूरदर्शिताश का प्रयास करार नहीं दिया, यह दावा भी किया कि इससे सुशासन बनाये आयाम दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने इस दूरदर्शी साहस के लाभों का बखान करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है, नीति निर्धारण से जुड़ी निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है औ संसाधनों के अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जनहित में अनेक अन्य लाभ हो सकते हैं यहां हम एक देश, एक चुनावश के प्रोजेक्ट के गुण-दोष बात नहीं कर रहे हैं। यह दूसरी बात है कि राष्ट्रपति के इस प्रोजेक्ट के गुणों के बखान में एक भी ऐसे तर्क का न हो थोड़ा निराश तो जरूर करता है, जो तर्क इस नारे के उठाने जाने के बाद से इसके पक्ष में पहले ही नहीं सुना जा चुका हो तरपाम चुनाव एक साथ कराए जाने से संसाधनों की बचत नीति निर्धारण में चुनाव संबंधी पार्बटियों के चलते पड़ वाली बाधाओं से उभरना, शासन में निरंतरता में बढ़ोत्तर आदि सब वही तर्क हैं जो बिना किसी ठोस साक्ष्य के अै वास्तव में बिना किसी ठोस तर्क के भी, इतनी बार दोहरा गए हैं कि सुन-सुनकर कान पक गए हैं।

जोड़ना ही चाहिए, इस तरह की मांग को तो शायद ज्यादा भी कहा जा सकता है, हालांकि ऐसा होना इस नारे के पक्ष तर्कों के सतहीपन को जरूर दिखाता है। खैर! असली बायह है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद अपनी सरकारश्वरूपी के शपरामर्शश्वरूपी से जिस तरह बंधा हुआ है, उसे देखते हुए राष्ट्रपति के अपनी सरकार के किसी फैसले का बचाव करने को किसी भी तरह से गलत न कहा जा सकता है। जहां तक एक देश एक चुनाव विप्रोजेक्ट का सवाल है, उस पर राष्ट्रपति मुर्मू की सरकार अंततः अपने अनुमोदन की मोहर ही नहीं लगा चुकी है, वहां विधेयकों के रूप में इससे संबंधित संशोधन प्रस्तावों का पिछले ही सत्र में संसद में पेश भी कर चुकी है। और इन विधेयकों को और विचार के लिए, संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेज भी जा चुका है। फिर भी, राष्ट्रपति द्वारा एक देश एक चुनाव का जोर-शोर से ढोल पीटे जाने में कानून व्यवस्थाओं के तकनीकी पहलू से चाहे कुछ भी गलत न हो, फिर भी संवैधानिक नैतिकता के पहलू से इस समस्यापूर्ण होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब तो यह सरकार के एक ऐसे फैसले का राष्ट्रपति द्वारा ढोल पीटे जाने का मामला है, जिस पर देश तथा जनमत के पूरी तरह बढ़े होने से किसी भी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व-राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार-प्रासमिति के अंतर्गत अपनी सिफारिशें देने से पहले उस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में देश की जितनी राजनीतिति

पाटिया को राय मिली थी, उस पर एक नजर भर डालने से ही, इस मुदे पर जनमत के गंभीर रूप से विभाजित होने का सच सामने आ जाता है। वास्तव में यह सच भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इस परियोजना के पीछे मुख्य संचालक, सत्ताधारी भाजपा ही है, हालांकि उसके लिए अपने सहयोगी दलों को घेर-बटोरकर इस प्रोजेक्ट के पक्ष में दिवस को पूर्व-संध्या में राष्ट्रपति के परंपरागत किसमारोही संबोधन का मामला था। कम से कम ऐसे संबोधन में राष्ट्रपति के अक्षरण: अपनी सरकार के लिखे को पढ़ने वाले जबूरी नहीं होनी चाहिए। कम से कम नकारात्मक विवेदन का उपयोग कर, राष्ट्रपति सरकार के विशेष रूप से ऐसे विवादास्पद तथा संसदीय प्रक्रियाधीन प्रोजेक्ट का ढो-



करना ना तुरकरता था। युग्म हराया पथ है कि यह साथ चुनाव संबंधी विधेयकों का विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना भी, इस मामले पर विचारांकी व्यापक भिन्नता को ही दिखाता है। यह संयोग ही नहीं है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह दूसरा ही मोका है, जब किसी विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। इस सिलसिले में यह याद दिलाना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए किए प्रस्तावित संशोधनों में, कई संविधान संशोधन भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में यह ऐसा प्रस्ताव है, जो वर्तमान रूप में संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ जाता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति के सरकार के फैसले के अनुमोदन के लिए दौड़ पड़ने की जल्दबाजी कम से कम बेढ़ तो जरूर ही कही जाएगी। हालांकि, इस संभावना को काल्पनिक ही कहा जाएगा, फिर भी बहस के लिए अगर हम यह मान लें कि संसद के सामने विचाराधीन संशोधन, विफल हो जाते हैं, तो एक देश एक चुनाव की राष्ट्रपति की इस जोरदार पैरवी का क्या होगा? याद रहे कि इस पैकेज में शामिल संविधान संशोधन के प्रस्तावों का, संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना, वैसे भी बहुत मुश्किल है। साफ़ है कि राष्ट्रपति हर एक लिहाज समस्यागूण परियोजना के साथ अपनी नाम जोड़ने की हड़बड़ी दिखा रही थीं। वह भी तब जबकि यह गणतंत्र नाम तो उनके जाता रहा। यह अपनी विधेयकों का विचार के लिए संयुक्त राष्ट्रपति के इस अधिभाषण में एक यही चीज विवादास्पद नहीं थी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अपनी सरकार के गरीबी तथा भुखमरी से देश और लोगों को उबराने के उपलब्धियोंसे के अतिरिक्त दावे तो किए ही, इसके साथ ही उन्होंने तथाकथित औपनिवेशिक मानसिकता व अवशेषों से उबरने के प्रयास के रूप में तीन नयी फैजदार संहिताओं का भी जिक्र किया। और इस सब के ऊपर से कुंभ के आयोजन के बहाने से इसका भी दावा किया कि शहमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारा जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ है। राष्ट्रपति के इन सभी दावों पर विवाद ह सकता है। लेकिन, गणतंत्र दिवस के समारोही मोके पर कम से कम एक देश, एक चुनावशक् के कर्कश विवाद में पड़ने का विवेक राष्ट्रपति को और उन्हें इस विवाद में ध्वेकलने का विवेक मोदी सरकार को दिखाना चाहिए था। लेकिन, दोनों ने ही ऐसे विवेक का प्रदर्शन नहीं किया, जो अपने 75 वर्ष पूरे करने के मौके पर भारतीय गणराज्य के दशा-दिशा की ओर एक कठोर इशारा है। वास्तव में ऐसा है एक और इशारा खुद भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होने व लेकर किया गया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर जैसा समारोही जोश शासन में दिखाई दिया था, उसके सौबां हिस्सा भी गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर नहीं दिखाई दिया।

मनस्तेरा की विस्तृति

यांत्रिक योजना के तहत प्रारंभिक दो वर्षों में बृद्धि व विकास का लकड़ा गतिशीलता में कमी लाने में महत्वात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस योजना ने जहां एक ओर ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने गांव के पास रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं अतरंजितीय प्रवास को कम किया है। साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति भी बढ़ी है। काम की तलाश में शरखों को जाने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी के भी आंकड़े सामने आए हैं। खासकर कोरोना संकट में जब ग्रामीण महानगरों से पलायन करके बड़ी संख्या में गांव की तरफलौटे तो इस योजना ने जीवनदायिनी भूमिका निभाई है। लेकिन पिछलाल ग्रामीण आजीविका के लिये जीवन रेखा कही जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक बार पिछे धन की कमी से जूझ रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासन में शुरू की गई मनरेगा योजना राजग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। वार्षिक वित्तीय संकट से जूँ रही मनरेगा योजना के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसके बावजूद 4,315 करोड़ मूल्य का वेतन भुगतान लंबित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 में इस योजना के केवल छ माह में ही 6,146 करोड़ का घाटा हुआ था। इसी तरह वर्ष 2022-23 में 89,400 करोड़ का संशोधित धनराशि का आवंटन मूल बजट से 33 प्रतिशत अधिक

जो कहतु ग्रामीण ने इस योजना तक उपलब्ध रूप से लिया है। हालांकि, इस प्रणाली को पारदर्शिता बढ़ाने के उपर्योग के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन ऐ कटम लाखों श्रमिकों के लिये आजीविका के मार्ग में बाधा बन गए। उल्लेखनीय है कि मनरेगा को ग्रामीण परिवारों के लिये आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक मांग संचालित योजना के रूप में तैयार किया गया था। निस्संदेह, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में देरोजगारी के संकट को ही ऊजागर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती काम की मांग औ शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की कमी के संकेत लगातार मिलते रहे हैं। निस्संदेह, गांवों में गरीबी उन्मूलन में मनरेगा के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। आसन्न बजट में इस योजना से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिये गंभीर प्रयास की जरूरत है। सरकार को मनरेगा के लिये एक व्यावहारिक बजट बनाना चाहिए। साथ ही योजना के पारदर्शी फियान्वयन के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्विवाद रूप से मनरेगा में मांग के अनुपात में धन का आवंटन लगातार कम हो रहा है। यही वजह है कि पंड वी कमी के चलते वर्ष के मध्य में अनुमानित संकट पैदा हो रहा है। जो नीति नियंताओं के इसके फियान्वयन के संरचनात्मक अंतर को दर्शाता है। निस्संदेह, इस नीतिगत विसंगति को दूर किया जाना चाहिए।

अंतिम सरकार के तहत बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक लहर

आशोष विश्वास

बांगलादेश में अर्थास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अनिवार्यचित अंतरिम शासकों का एक समूह पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए बेताब है। उस पाकिस्तान से जिससे उनका देश केवल पांच दशक पहले हिंसक तरीके से अलग हुआ था। अपने स्वयं के (तत्कालिक) इतिहास के एक अजीब उलटफेर में, बांगलादेशियों ने दक्षिण एशिया में एक स्वतंत्र, सम्प्रभु देश के रूप में अस्तित्व में रहने और कार्य करने में स्पष्ट रूप से असमर्थता दिखाई है। तथ्यों पर गौर करें 1947 में बांगलादेशियों को, पूर्वी पाकिस्तानी होने के नाते, इस्लामी गणराज्य के पूर्वी हिस्से में गरीब, तीसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। अपने शोषण से तंग आकर, उन्होंने 1970-71 में पाकिस्तान को पूरी तरह से भूर्धे

करते हुए अलग होने का फैसला किया। बाद के दशकों में कभी-कभार तनाव के बावजूद, वे मोटे तौर पर भारत के साथ जुड़े रहे - कुछ महीने पहले तक। अपनी आजादी हासिल करने के लिए, उन्होंने करूर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष करते हुए जान गंवाने के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अब अचानक, 2025 में, डॉ. मोहम्मद यूनस और उनकी टीम के नेतृत्व में कुछ बांग्लादेशियों ने फैसला किया है कि एक बार पिस से, वे पाकिस्तानियों के साथ रहना बहेतर



और यहां तक कि गैर-निवासी भारतीय जिनका भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है, बांग्लादेश को परेशान करने वाली कई प्रणालीय गति समस्याओं के लिए आतोचना का शिकार हो रहे हाल ही में पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख की बांग्लादेश विवादास्पद यात्रा को प्रायोजित किया, जिसवाप्रति बहुत अच्छी नहीं है। भारत-बांग्लादेश

संबंधों में मौजूदा ठंड को देखते हुए, अधिकांश ढाका-आधारित टिप्पणीकरों विश्लेषकों ने ढाका द्वारा दिल्ली को भेजे जा रहे मजबूत, अभिन्न संकेतों पर टिप्पणी की है। आईएसआई का यह दौरा ढाका में पहले ही बहुत धूमधाम से घोषित किये जा चुके कुछ अन्य कदमों के मद्देनजर हुआ है। बांग्लादेश का कार्यवाहक शासन पाकिस्तान में शाहबाज शरीफके नेतृत्व वाली सरकार से दोस्ती करने की जल्दी में है। इसने पाकिस्तानी आगंतुकों के लिए वीजा नियमों में पहले ही ढील दे दी है और उर्दू के प्रचार के लिए बांग्लादेश में और अधिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर रहा है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और गठजोड़ को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नयी पाठ्य पुस्तकें, जिनमें दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान, ताजुद्दीन अहमद या यहां तक कि जियाउर रहमान द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई गई भूमिका को शामिल नहीं किया गया है, छात्रों के बीच वितरित की जा रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की सहायक भूमिका और योगदान, रहमान की अवामी लीग को उसका समर्थन, भारत-पाक युद्ध के दौरान कम से कम 10,000 भारतीय सैनिकों की शहादत को कम महत्व दिया गया है।

संक्षेप में अपने उत्तर-चाढ़ाव भे अभिन्नत्व के तरह से अघोषित शअधिकारियोंश् के एक समूह द्वारा अपने स्वयं के बहुत ही सर्किष्म इतिहास का पिछ से लिखने- और यहां तक कि उसे गल साबित करने- के लिए मजबूर किया गया है। ऐसा तो पूर्व जनरल इरशाद के कार्यकाल में भ नहीं हुआ था, जिन्होंने देश में आभासी सैन शासन का दौर चलाया था। विश्लेषकों को य चिंताजनक लगता है कि बांग्लादेश के वर्तमान शअधिकारीश् जो सर्वेधानिक रूप से किसी वं प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, अपने घरेलू कट्टरपंथ इस्लामवादी लॉबी को खुश करने के लिए अपने समकालीन इतिहास के सुप्रलेखित स्थापित तथ्य को विकृत करने या दबाने से पीछे नहीं होते हैं। यह जमाती समर्थक ताकतों का वह वर्ग है ज हमेशा पाकिस्तान के करीब रहा है, जो बांग्लादेश में उभरने वाले एक सख्त, शरीयत-प्रधा व्यवस्था के सपने संजोये हुए है। अगर भारत प्रभावशाली वर्ग इस बात से परेशान हैं, तो य बहुत बुरा है- उन्हें नये बांग्लादेश से निपटन होगा। यही अब तक यूनिस और उनकी टीम ढाका से निकलने वाला व्यापक संदेश है। सच्चा कुछ अलग है, और अप्रिय भी। अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों भारत, पाकिस्तान, और चीन - र सम्बंध के मामले में वर्तमान बांग्लादेश सरक का गवर्नर दक्षिण अशिया के अन्य देशों नेपाल य

